SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, the Government of India will have to spell out its stand. What is your stand on this issue? The war was over in 2009 and the Sri Lankan Tamils are yet to get justice. And, the Government of India will have to play a pro-active role. We are a neighbouring country. We are responsible for what is happening in Sri Lanka. What is the stand of the Government of India? The Government should spell it out. Thank you.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the Zero Hour submission made by Dr. V. Maitreyan.

SHRI A.K. SELVARAJ (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission of Dr. Maitreyan.

SHRI K.R. ARJUNAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the submission made by Dr. Maitreyan.

DR. R. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the submission made by Dr. Maitreyan.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Majeed Memon. Not present. Now, Smt. Rajani Patil.

Problems being faced by farmers in various parts of the country, particularly in Maharashtra due to unseasonal rains

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): सर, हाल ही में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, खास तौर से मराठवाड़ा के बीड, लातूर और उस्मानाबाद क्षेत्र में बहुत बड़ी ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश हुई है। उसकी वजह से बहुत बड़ी मानवीय जीवन हानि हुई है और जानवर भी मर गए हैं। सर, इस क्षेत्र में मालूम होगा, मैंने इस मुद्दे को बहुत बार उठाया है। वे चार साल अकाल से मारे गए हैं, अकाल से पीड़ित हुए हैं। स्थिति इतनी खराब हुई कि हमारे क्षेत्र में पीने के लिए भी पानी वेस्टर्न महाराष्ट्र से ट्रेन से लाना पड़ा। सर, इसके बाद नोटबंदी की वजह से हमारे किसान मारे गए। क्योंकि नोटबंदी की वजह से बैंक्स पैसे कम दे रहे थे, तो हमारी जो फसल आई थी, उस फसल को बेचने के लिए उनको प्राइवेट वेंडर्स के पास जाना पड़ा और जो प्राइवेट लोग थे, चाहे सोयाबीन हो या कपास हो, उसके आधे से भी कम कीमत में उनको अपनी वह फसल बेचनी पड़ी। रबी बोने का जो सीजन होता है, उसमें बीज लाना हो, खाद लानी हो या खेती के काम करने हों, उसके लिए भी उनके पास पैसा नहीं रहा और अब 4 दिन पहले जब बेमौसमी बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई है, उसके कारण उस क्षेत्र के लोगों का, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर, सभी तरफ से पीड़ित यह किसान आज परेशान है और वह गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है।

उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जब भी हम चुन कर आएँगे, तो हम पहला डिसीज़न यह लेंगे कि हम किसानों को ऋण मुक्त करेंगे। सर, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, सिर्फ बाकी स्टेट्स के ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र सहित सारे देश के किसानों की ऋणमुक्ति होनी चाहिए। जिस तरह से यूपीए गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ रुपये की ऋणमुक्ति की थी, उसी तरह से उनको करना चाहिए और इस देश के किसानों को राहत देनी चाहिए। यह जो बेमौसमी बारिश होती है, उसमें जब मौत हो जाती है, चाहे वह जानवरों की हो या मानव की हानि हो, जीवन की हानि होती है, उसके लिए बीमा संरक्षण होना चाहिए।

तीसरी बात, हमारा जो धान है, जो बेमौसमी फसल है, उसके लिए उसको बीमा संरक्षण नहीं मिलता है, तो उसको बीमा का संरक्षण देना भी बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरे देश का जो किसान वर्ग है, बहुत ही पीड़ित है। जैसे अभी आत्महत्या की बात कही गई, तो हमारे क्षेत्र में, महाराष्ट्र में एक साल में 3,000 आत्महत्याएँ हो गईं। तो इस तरह से किसानों को परेशानी हो रही है। जब बड़े-बड़े धन्नासेठों को छोड़ देते हैं, उनको ऋणमुक्त करते हैं, वे देश छोड़ कर भाग जाते हैं, तो फिर हमारे जो गरीब किसान हैं, वे अपना खेत छोड़ कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, अपना घर-गाँव छोड़ कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, उनको ऋणमुक्त करने की आवश्यकता है। अगर किसान जिएँगे, तो ही भारत देश जिएगा, इतना ध्यान रखना जरूरी है। किसानों की सम्पूर्ण ऋणमुक्ति करना, यह हमारी माँग है, जो मैं आपके माध्यम से करना चाहती हूँ।

श्रीमती रेणुका चौधरी (आन्ध्र प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

कुमारी शैलजा (हरियाणा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्रीमती वानसुक साइम (मेघालय): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्रीमती वंदना चव्हाण (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री बी.के. हरिप्रसाद (कर्णाटक): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री तपन कुमार सेन (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter issued by the hon. Member.

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: We also associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

Alleged neglect of forts of Shivaji and demand to include them in World Heritage List

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, there is a neglect of the forts of Chhatrapati Shivaji Maharaj and their inclusion in the World Heritage List and branding in the UNESCO. The military might and valour of Chhatrapati Shivaji Maharaj are inscribed deep into the hearts and minds of all the Indians. The country has given him due honour, which is evident from the fact that his statue on the horseback stands installed in the Parliament Campus. There are 350 forts, directly or indirectly, associated with Chhatrapati Shivaji Maharaj. The people of Maharashtra are emotionally attached to everything which is associated with Shivaji Maharaj. Therefore, they all desire that the forts associated with him are preserved and developed as invaluable heritage of the country. But, I am pained to point out that the forts of Chhatrapati Shivaji Maharaj, including those under the control the ASI, are in a state of neglect, despite their immense historical and cultural importance. Further, these forts are yet to be developed as tourist attractions of the country.

The annual Budgetary allocation for each of these forts is far from satisfactory and it seems that step-motherly treatment has been given to them in comparison to other important protected monuments.

I, however, congratulate the Central Government for keeping some of the protected monuments like Taj Mahal, Agra Fort, Kumbhalgarh, Ajanta Caves, etc. under the ASI as per international standards. Leave all the forts of Shivaji Maharaj, the Raigadh fort -where he was coronated as 'Chhatrapati', *i.e.* Sovereign King - is compared with the biggest fort in the world, the GIBRALTAR, and is also called as Gibraltar of the East. But it is most unfortunate that even basic facilities do not exist at this magnificent and massive fort. Needless to say, former President Giani Zail Singhji, Prime Ministers, Indira Gandhiji, Atal Behari Vajpayeeji and Narendra Bhai Modiji had visited Raigadh fort and witnessed its grandeur. May I also point out that the ASI has not been judicious in identifying the monuments and in submitting proposals for their inclusion in the World Heritage List to the UNESCO? Although it is a matter of great pride that six forts of Rajasthan have been included in the World Heritage List, it is painful to say that the forts of Maharashtra have not been included in the World Heritage List. I request the Government, through you, Sir, that immediate steps must be taken to submit a proposal for including the forts